नई दिल्ली, मंगलवार, 2 सितंबर 2014

वित्तीय समावेश अर्थव्यवस्था को गति देगा असंगठित क्षेत्र

'असंगठित क्षेत्र के लिए वित्तीय ढांचा जरूरी'

▸ दिल्ली में आयोजित पहले गोल मेज सम्मलेन में शामिल हुए देशभर के व्यापारिक संगठन

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। विख्यात अथशास्त्री और वित्तीय सलाहकार एस गुरुमूर्ति ने सोमावर नई दिल्ली में आयोजित एक गोल मेज सम्मेलन में असंगठित क्षेत्र के लिए अलग से एक मजबूत वित्तीय ढांचे की जोरदार वकालत करते हुए कहा की असंगठित क्षेत्र ने राष्ट्रीय जीडीपी, रोजगार, निर्यात और घरेलू उत्पादन के क्षेत्र में कॉर्पोरेट सेक्टर से कहीं अधिक योगदान दिया है और इस दृष्टि से इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

गोल मेज सम्मेलन का आयोजन असंगठित क्षेत्र के विभिन्न वर्गों, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, ट्रक ऑपरेटर,लघु उद्यमी,स्वयं उद्यमी, हॉकर्स, महिला उद्यमी, मजदूर आदि के राष्ट्रीय संगठनों द्वारा गठित एक्शन कमेटी फॉर फॉर्मल फाइनेंस फॉर नॉन कॉर्पोरेट स्माल बिजनेस ने किया था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गुरुमूर्ति ने कहा की नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी है जो प्रतिवर्ष लगभग 6 .28 लाख करोड़ रुपए की राशि जोड़ता है लेकिन फिर भी इस सेक्टर की वित्तीय आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है जिससे अर्थव्यवस्था की प्रगति भी प्रभावित हुई है। बैंकिंग संस्थान इस सेक्टर के केवल 4 प्रतिशत हिस्से को ही वित्त उपलब्ध करा पाए। उन्होंने कहा की गैर संगठित और गैर कृषि के इस क्षेत्र में लगभग 5 .77 उद्यमी व्यवसाय काम कर रहे हैं जो लगभग 46 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे है जिसमें से 24 करोड़ लोग स्वयं उद्यमी है। उन्होंने यह भी कहा की नॉन कॉर्पोरेट उद्यमों के लगभग 61 फीसदी मालिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उन्होंने कहा की भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से औपचारिक बनाने के लिए नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का वित्तीय समावेश बेहद जरूरी है। गुरुमूर्ति ने जोर देते हुए कहा की इस क्षेत्र के 90 प्रतिशत लोगों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है क्योंकि इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अपंजीकृत उद्यमों के रूप में काम करता है और बैंकों द्वारा ऋण देने के जटिल नियमों के कारण बैंकिंग संस्थान इस सेक्टर को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करा पाते। यहां तक की पंजीकृत लघु, सूक्ष्म एवं मंझले उद्योगों को भी बैंकों से वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है, ऐसे में इस क्षेत्र को बैंकों से कर्ज मिलना बेहद मुश्किल है। उन्होंने स्माल बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज अथवा संस्थान के रूप में इस क्षेत्र के लिए अलग से एक वित्तीय ढांचा बनाया जाना चाहिए। एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रवीन खण्डेलवाल ने बताया की इसी तरह के 10 गोल मेज सम्मेलन अगले दो महीने में मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, बैंगलौर, हैदराबाद, कोचीन, नागपुर, भोपाल और कानपुर में आयोजित किए जाएंगे। वहीं, दूसरी ओर एक्शन कमेटी देश के विभिन्न तीस शहरों में जन अदालत भी लगाएगी जिनमें नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े वर्गों के लोग वर्तमान बैंकिंग एवं वित्त संस्थानों से वित्तीय कर्ज मिलने की स्तिथि के बारे में बताएंगे। इन दोनों कार्यक्रमों से वित्त क्षेत्र की जमीनी हकीकत का पता चलेगा।

गोल मेज सम्मेलन और जन अदालत के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक्शन कमेटी एक श्वेत पत्र तैयार करेगी जिसे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर को दिया जाएगा। श्वेत पत्र सभी राजनैतिक दलों के शीर्ष नेताओं और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को भी दिया जाएगा।

गोल मेज सम्मेलन में मजबूत वित्तीय ढांचे की जोरदार वकालत करते एस गुरुमूर्ति।